



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART II—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 9, 2017/माघ 20, 1938

No. 37]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 9, 2017/MAGHA 20, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2017

प्रकरण सं. ओ आई—06/2017

(मूल जांच)

विषय : चीन, जापान, दक्षिण अफ्रीका और ताईवान में उत्पादित या निर्यातित “मिथाइल इथाइल कीटोन अथवा एमईके” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत

फा. सं. 14/26/2016-डीजीएडी।—मै.सीटेक्स पैट्रोकेमिकल्स लि० (जिसे आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष पाटनरोधी जांच आरंभ करने और चीन, जापान, दक्षिण अफ्रीका और ताईवान (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) में उत्पादित या वहां से निर्यातित मिथाइल इथाइल कीटोन के आयातों के विषय में पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और चूंकि, प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि संबद्ध वस्तुओं, संबद्ध देशों में उत्पादित या निर्यातित, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन तथा क्षति के बीच सांयोगिक संबंध के पर्याप्त प्रमाण पाटनरोधी जांच को उचित ठहराने के लिए विद्यमान हैं, एतद्वारा, प्राधिकारी द्वारा आरोपित पाटन और इससे पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 की शर्तों में परिणामिक क्षति, आरोपित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने, जो यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होता, जांच आरंभ कर दी है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक के रूप में मै0 सीटेक्स पैट्रोकेमिकल्स लि0 (जिसे आगे घरेलू उद्योग या आवेदक कहा गया है) द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता कंपनी भारत में संबद्ध वस्तुओं की एकमात्र उत्पादक कंपनी है। याचिकाकर्ता ने विषयगत देशों में से कुछ से संबद्ध वस्तुओं का थोड़ी मात्रा में आयात किया है किंतु याचिकाकर्ता द्वारा तैयार किया गया आयात भारत में कुल मांग, भारत में किए जाने वाले कुल आयात और जांच की अवधि के दौरान इसके कुल उत्पादन की तुलना में नगण्य है। याचिकाकर्ता ने घोषित किया है कि वह न तो संबद्ध देशों में संबद्ध सामान के किसी निर्यातिक या उत्पादक से अथवा न ही भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है। अतः प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि आवेदक नियम 2(ख) में यथापरिभाषित के अनुसार अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और यह कि आवेदन पहले नियमावली के नियम 5(3) की शर्तों में प्रचलित मानदंड को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

4. विद्यमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद मिथाइल ईथाइल कीटोन (एम ई के) है। एम ई के फार्मूला CH₃C(O)CH₂CH₃ के साथ एक कार्बनिक मिश्रण है और संचयी विषवैज्ञानिक(टॉक्सीलॉजिकल) प्रोपर्टीज सहित एसीटोन जैसी गंध वाला सफेद जल जैसा अत्यधिक वाष्पशील दृव्य है। मिथाइल ईथाइल कीटोन एक सर्वाधिक बहुमुखी दृव्य है जो पदार्थों की बड़ी रेंज को घुलनशील बनाने में सक्षम है। यह रंगहीन कीटोन की तीखी, मीठी गंध वाला पदार्थ है जो बटरस्कॉच और एसीटोन की याद दिलाता है। यह बड़े पैमाने पर औद्योगिक रूप से उत्पादित किया जाता है और प्रकृति में ट्रेस अमाउंट में भी पाया जाता है। यह जल में घुलनशील है और सामान्यतः एक औद्योगिक विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय-29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। पीयूसी का सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय-29 के अंतर्गत एक विशिष्ट एच एस कोड 29141200 है। सीमाशुल्क वर्गीकरण मात्र सांकेतिक है और यह इस जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

6. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामान और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित सामान के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसाकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मिथाइल ईथाइल कीटोन और संबद्ध देशों से आयातित अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, मूल्य निर्देशन, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण तुलनीय है। आवेदक ने आगे दावा किया है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और अतः दोनों को नियमावली के तहत “समान वस्तु” के रूप में माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु के रूप में मानते हैं।

जांच किए जाने वाले देश

7. वर्तमान जांच में सम्मिलित देश चीन, जापान, दक्षिण अफ्रीका और ताइवान (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) हैं।

सामान्य मूल्य

8. याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू मूल्यों पर सार्वजनिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना के अभाव में संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान उत्पादन लागत, उन देशों में कच्ची सामग्रियों और सुविधाओं की कीमतों पर विचार करते हुए, घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत और विधिवत रूप से समायोजित विक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय जमा तर्कसंगत लाभ पर विचार करते हुए लगाया गया है।

निर्यात कीमत

9. याचिकाकर्ता ने संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात मूल्य का डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर दावा किया है। समायोजन का दावा समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्रेशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और एक्स-फैक्ट्री स्तर पर निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए बैंक प्रभार के आधार पर किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए निर्यात मूल्य के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

पाटन मार्जिन

10. सामान्य मूल्य की एक्स-फैक्टरी स्तर पर निर्यात मूल्य के साथ तुलना की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य एक्स फैक्टरी निर्यात मूल्य से अधिक है जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से निर्यातिकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं को पाटित किया जा रहा है और पाटन मार्जिन उक्त न्यूनतम सीमा से अधिक है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

11. याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिए विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने कुल रूप में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप और भारत में उत्पादन और मांग के संबंध में, मूल्य ह्रास और मूल्य से कम कीमत पर विक्री और परिणामस्वरूप लाभ की शर्तों में नियोजित पूंजी पर आय और घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह पर विपरीत प्रभाव के संबंध में प्रमाण उपलब्ध कराए हैं। पाटनरोधी जांच को आरंभ किए जाने को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा वहन की जा रही “क्षति” के पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

12. जांच की प्रस्तावित अवधि (पी ओ आई) जुलाई, 2015-सितंबर, 2016 (15 महीने) है। तथापि, क्षति जांच अवधि अप्रैल 13-मार्च 14, अप्रैल 14-मार्च 15, अप्रैल 15-मार्च 16 तथा जांच की प्रस्तावित अवधि को सम्मिलित करने के लिए विचारित और प्रस्तावित की गई है।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देशों में ज्ञात विशेषज्ञों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, उत्पाद के साथ संबद्ध भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में व निर्धारित तरीके से प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत कर सकें और अपने विचार नीचे दिए गए पतों पर प्राधिकारी को भेज सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना निर्धारित प्रपत्र और तरीके में नीचे दी गई समय सीमा के भीतर भेज सकता है।

समय-सीमा

15. वर्तमान जांच से संबंधित कोई जानकारी और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए ताकि वह अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से अनधिक ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी तक पहुंच सके। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज करा सकते हैं।

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे तत्कालीन मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और अपनी प्रश्नावली के प्रत्युत्तरों को और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन के संबंध में अपनी टिप्पणियों को इस जांच के आरंभ होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर दायर करें।

अगोपनीयता आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. यदि प्रश्नावली के प्रत्युत्तर/प्रस्तुतियों के किसी भाग पर गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो पृथक सैटों में प्रस्तुत करना होगा (क) गोपनीय के रूप में चिन्हित (शीर्षक, सूचकांक, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) और (ख) अगोपनीय के रूप में चिन्हित अन्य सैट (शीर्षक, सूचकांक, पृष्ठों की संख्या आदि सहित)। आपूर्ति की गई सारी जानकारी को प्रत्येक पृष्ठ से ऊपरी भाग पर स्पष्ट रूप से “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए।

18. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत करानी होंगी।

19. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचनाप्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/अथवा ऐसी सूचना का सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

20. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

21. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने के बाद, सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में उचित कारण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद, प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डा. इंद्र जीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2017

Case No. OI—06/2017

(Original Investigation)

Subject : Initiation of Antidumping investigation concerning imports of “Methyl Ethyl Ketone or MEK” originating in or exported from China, Japan, South Africa and Taiwan.

F.No. 14/26/2016-DGAD.— M/s Cetex Petrochemicals Ltd (hereinafter referred to as the petitioner) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of Methyl Ethyl Ketone (hereinafter also referred to as either “MEK” or the subject goods), originating in or exported from China, Japan, South Africa and Taiwan (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. And whereas, on finding *prima facie* that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Anti-Dumping Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The application has been filed by M/s Cetex Petrochemicals Ltd., (hereinafter referred to as the domestic industry or the applicant), as producer of the subject goods in India. The petitioner company is the sole producer of the subject goods in India. The petitioner has imported small quantities of subject goods from some of the subject countries but imports made by the petitioner are negligible in terms of total demand in India, total imports into India and its total production during the period of investigation. The petitioner has declared that it is not related either to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries or any importer of the subject goods in India. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

4. The product under consideration in the present petition is Methyl Ethyl Ketone(MEK). MEK, is an organic compound with the formula CH₃C(O)CH₂CH₃ and is a water white, highly volatile liquid having Acetone-like odour with no cumulative toxicological properties. Methyl Ethyl Ketone is one of the most versatile solvents, capable of dissolving a wide range of substances. This colorless liquid ketone has a sharp, sweet odor reminiscent of butterscotch and acetone. It is produced industrially on a large scale, and also occurs in trace amounts in nature. It is soluble in water and is commonly used as an industrial solvent.

5. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The PUC has a specific HS code 29141200 under Chapter 29 of Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

Like Articles

6. The petitioner has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the petitioner. As submitted by the petitioner, Methyl Ethyl Ketone produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The petitioner has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the petitioner in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries

Subject Countries

7. The countries involved in the present investigation are China, Japan, South Africa and Taiwan (referred to as the "subject countries").

Normal Value

8. The petitioners have submitted that in the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject countries the Normal values in the subject countries have been estimated on the basis of cost of production; taking into account prevailing international prices of raw materials and cost of utilities in subject countries, conversion costs of the domestic industry, duly adjusted on account of selling, general & administration expenses, plus reasonable profit.

Export Price

9. The petitioner has claimed export price for the subject goods on the basis of DGCI&S published data. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges to arrive at net export price at ex-factory level. There is sufficient *prima facie* evidence with regard to the export price claimed by the petitioner.

Dumping Margin

10. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient *prima facie* evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margin is estimated to be above *de minimis*.

Injury and Causal Link

11. Information furnished by the petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The petitioner has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of profits, return on capital employed, and cash flow of the domestic industry. There is sufficient *prima facie* evidence of the ‘injury’ being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation (POI)

12. The proposed period of investigation (POI) is July 2015 – September 2016 (15 Months). However, the injury investigation period has been considered and proposed to cover the periods April 13-March14, April 14-March15, April 15-March 16 and the proposed period of investigation.

Submission of information

13. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce,
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.**

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

15. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry’s application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

18. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

23. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

24. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr. INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority